case of Toyo and also utilise the possibilities of the planning and development division of the Fertiliser Corporation?

SHRI D. K. BOROOAH: Yes, Sir.

श्री नाथू राम मिर्धा : आपने जिन 10–12 यूनिट को लगाने के बारे में बतलाया है, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो फास्टफेट और पाइराइट्स का अतुल भण्डार है उसके उपयोग के बारे में भी विचार किया है ? आज फास्फेट फर्टिलाइजर इम्पोर्ट किए जाते हैं, उस इम्पोर्ट को रोकने की दृष्टि से क्या राजस्थान के इन मिनरल्ज के उपयोग करने की बात ख्याल मे रखी गई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : राक-फास्फेट के बारे मे एक विशेष चर्चा हो रही है । इसमें कोई सन्देह नही है कि राजस्थान मे राक-फास्फेट और पाइराइट्स का काफी भ डार है, लेकिन यह काम क्या रूप लेगा, इस बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नही होगा ।

Lease of Fallow Land along Railway track to Railway Employees for Growing Food Crops

*752 SHRI J G. KADAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the former Railway Minister had announced in Lok Sabha that the fallow land along the Railway tracks will be given on temporary lease to the Railway employees for growing food crops;

(b) if so, how many hectares of such land was given on lease in the years 1971-72 and 1972-73 and how many employees have taken the advantage of the scheme; and

(c) what is the result of this scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes Sir, the former Railway Minister had announced that the surplus cultivable railway land will be used for grow more food and other purposes by allotting such land to Railway employees.

(b) and (c). The information i being collected and will be placed on the table of the House.

SHRI J. G. KADAM: How much time will the hon. Minister need for placing the information on the Table of the House?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I cannot give a definite date but I think the beginning of the next session.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री की इस प्रकार की घोषणा के बावजूद 1971–72 और 1972–73 मे गैर रेलवे मजदूरों को भी रेलवे की इस तरह की जमीन लीज पर दी गई है ? अगर दी गई है तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ऐसा हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी जमीन दी गई है । इसमें कोई शक नही है कि कुछ जमीन सूबाई सरकारो को दी गई हैं, उन्होने उसका इस्तेमाल किया है और कुछ जमीन उन लोगों को भी दी गई है जो रेलवे के मुलाजिम नही है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व रेल मंत्री ने जो नीति निर्धारित की थी, उसमें केवल रेल मजदूरों और रेल

कर्मचारियों की बात कही गई है। मैं जानना चाहूंगा—क्यों नहीं, सरकार रेलवे की ऐसी भूमि को उन लोगों को दे, जो भूमिहीन हैं और जो किसी सर्विस में भी नहीं हैं ?

श्री मुहम्मद शकी कुरेशी : रेलवे के पास इस वक्त जो जमीन फालतू पड़ी हैं और जो इस्तेमाल नहीं हुई है, हमारा विचार है कि उसमें सबसे पहले तरजीह उन ग्रैजुएट्स को दी जाय जो एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटीज से निकले हैं और उनको नौकरी नहीं मिली हैं। वे अगर चाहें तो रेलवे की जमीन ले सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को दी जाय जिन के पास जमीन नहीं है, वे भी इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बाद रेलवे एम्पलाइज उस जमीन का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं ।

SHRI MUHAMMED KHUDA BUKSH: May I know from the hon. Minister as to what is the quantum of land we have decided to give to the agricultural landless etc.?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: It is about 35,531 acres of land.

SHRI MUHAMMED KHUDA BUKSH: I would like to know from the new Railway Minister as to whether he is thinking of leasing out the railway spare lands to the agricultural landless labourers or not?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): At this stage I have no information to depart from the present policy.

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार को ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों के नाम से जमीन लेकर खुद का अधिकार उस पर जमाये हुए बैठे हैं और सारी फसल खुद ले लेते हैं ?

श्री मुहम्मद शकी कुरेशी : ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : एक रेल कर्मचारी को डेढ़ बीघा जमीन दी जाती है जबकि बीस-बीस बीघे जमीन लेकर वह बैठे हुए हैं ।

SHRI MADHURYYA HALDAR: Last year when this question was raised by Shri Vajpayee, the then Railway Minister, Shri Hanumanthiya said that the agricultural land by the railway side would be distributed to the local landless but preference will be given to the scheduled castes and scheduled tribes.

Now, the Railway Minister, Shri Qureshi is giving us a different story. I want to know whether it is the policy that the railway employees are taking the cultivable land on lease which is lying by the railway station. They are leasing it at a higher rate, that is, at Rs. 100 per bigha.

I want to know whether they have changed this policy or not.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Out of a total of 1,17,000 acres of land, the Railways have given about 32,163 acres to the railway employees. We give preference to certain people if they want to have the land nearer their home. As regards the land which is available with the railways, the policy, as enunciated to-day is that we shall give preference to the unemployed agricultural graduates and to the landless people and to the railway employees who want to cultivate.